देश भक्ति का प्रमाण पत्र!

संसद में 'असहिष्णुता' पर चल रही बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर सबसे पहले कहावत याद आती है वह है 'नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने'।

ऐसा क्यों है कि उनकी बातों को सीधे उस तरह से नहीं लिया जा सकता है जैसे वे कही गयी हैं। वे पिछले कुछ वर्षों से अपनी छवि का कायान्तरण इस तरह से करने की कोशिश करते रहे हैं कि सब संतुष्ट हो जायें। इनमें उनके समर्थक से लेकर उनके गुजरात में भयाक्रांत लोग, सभी शामिल हैं।

आम चुनाव से पूर्व गुजरात में इसके लिये उन्होंने सद्भावना उपवास से लेकर 'टोपी' नहीं पहनने तक की सभी कवायदें कीं। उन्होंने ऐसे व्यवहार किया मानो राजनेता से संत बन गये हैं। परंतु संसद में वे अब ऐसे बन गये हैं कि मानो परम संत हो गये हों। अपने भाषण में परम संत ने कई मज़े की बातें कीं। सबसे मजे की बात है कि उनका यह प्रमाणपत्र जारी करना कि किसी को भी अपनी देशभक्ति को साबित करने की जरूरत नहीं है। देशभक्ति साबित करने में इस देश में यदि सबसे अधिक मुश्किल आती है तो उसी कुल को आती है जिसके वे स्वयंसेवक हैं।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भारतीय आज़ादी की लड़ाई में कोई सकारात्मक भूमिका नहीं रही है। उल्टे उन्होंने अपनी पोशाक खाकी निकर से ब्रिटिश पुलिस के सिपाहियों जैसा ही भान दिया। और कमोवेश ऐसी भूमिका निभाई कि बाद में उसकी चर्चा करने पर स्वयं सेवक भड़क उठते रहे हैं। हेडगेवार से लेकर वाजपेयी का इतिहास ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के सामने समर्पण का इतिहास है। यही बात संघ द्वारा परम पूज्य वीर सावरकर की भी रही है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री कहते हैं देशभक्ति साबित करने की जरूरत नहीं है। यह बात संघ के कार्यकर्ताओं व समर्थकों के लिये ठीक जान पड़ती है।

देशभक्ति का प्रमाण पत्र ऐसे लोग देश में दूसरों से मांगते रहे जिनका जन्म से लेकर आज तक पूरा इतिहास ही साम्राज्यवाद (खासकर आज़ादी कि बाद अमेरिकी साम्राज्यवाद) के सामने समर्पण हो रहा है। इनका हाल ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा संघी प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा में दो शब्द बोल दें तो ये उनका ऐसा प्रचार करते हैं मानों इन्होंने क्या हासिल कर लिया। देश के अखबारों से लेकर टेलीविजन में सुर्खियों की झड़ी लग जाती है। यह कैसी देशभक्ति है कि यह अपना प्रमाणपत्र उस देश से हासिल करती है जो दुनिया में देशों की आज़ादी का सबसे बड़ा दुश्मन है।

नरेन्द्र मोदी की सरकार ने बिहार चुनाव में मिली जबरदस्त हार के बाद दुनिया में भारत के शेयर बाजार को यह संदेश देने के लिये कि उनकी सरकार का आर्थिक सुधार का कार्यक्रम धीमा नहीं पड़ा है, विभिन्न क्षेत्रों में सौ फ़ीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की छूट दे दी। ओबामा जी की प्रशंसा इस सब के बाद ही मोदी जी को नसीब हुयी है। जो व्यक्ति देश के प्राकृतिक संसाधनों से लेकर देश के मज़दूरों-किसानों के शोषण की विदेशी पूंजी को बेलगाम छूट दे रहा हो वही व्यक्ति कहता है देशभक्ति साबित करने के लिये किसी को भी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक बात है। एकदम ठीक बात है कि यह देशभक्ति साबित करने का सिलसिला एकदम बंद होना चाहिये।

आज देशभक्ति साबित करने के लिये भारतीय शासकों को भारत की जनता से पाकिस्तान-बांग्लादेश के खिलाफ़ नारे लगवाने बंद करने चाहिये। नेपाल में माहौल खराब करने के लिये दाव-पेचों के समर्थन की मांग नहीं करनी चाहिये। भारत के शासक यदि ऐसा कर देते हैं तो कम से कम फ़िर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वह देशभक्त है। भारत में आज देशभक्त होने का एक ही अर्थ है कि कौन भारत के पड़ोसी देशों के खिलाफ़ कितनी आग उगल सकता है। इसी तर्ज पर कौन भारत के मुसलमानों को देश को छोड़कर जाने के लिये कितने उग्र ढंग से कह सकता है। इस अर्थ में देश के प्रधानमंत्री को यदि कहना था तो यह कहना चाहिये था कि किसी को भी किसी से देशभक्ति के प्रमाणपत्र को मांगने का दुस्साहस नहीं करना चाहिये। मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, प्रवीण तोगड़िया जैसे कलुषित संघीय विरासत को ढोने वालों के अंदर यह हिम्मत कहां से आती है कि वे देश में किसी से देश भक्ति का प्रमाणपत्र मांगे।

आज देश भक्ति का सच्चा अर्थ है तो यह कि देश को साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराने के लिए तीव्र संघर्ष छेड़ा जाय। विदेशी पूंजी को तुरंत जब्त किया जाय। विदेशी कर्जों को लौटाने से एकदम इंकार किया जाय। उन सभी देशों से बराबरी, परस्पर सम्मान, सहयोग के आधार पर एकजुटता कायम की जाय तो साम्राज्यवाद से उत्पीड़ित-शोषित हैं। इसी तर्ज पर देश के भीतर साम्राज्यवाद के सारे पिट्ठुओं को देशभक्ति का सही पाठ पढाया जाय। इनको देश के साथ गद्दारी करने की यथोचित सज़ा दी जाय। साम्राज्यवाद-परस्ती का जिनका इतिहास और वर्तमान रहा हो उनको सबक सिखाने के लिये जिस दिन भारत की जनता जागेगी वह दिन आज के 'देशभक्तों' की कयामत का दिन होगा।

-नागरिक

टोकाई ऑटो के श्रमिकों ने बढ़ा ग्रेड मांगा तो बाऊंसरों का हमला, पुलिस में केस

फ़रीदाबाद (म.मो.) जापानी पूंजी के सहयोग से चलने वाली टोकाई इम्पीरियल ऑटो का एक प्लांट सेक्टर 58 तथा दूसरा गदपुरी (पलवल) में स्थित है। दोनों प्लांटों में 450 से अधिक श्रमिक काम करते हैं। इनमें 80 प्रतिशत महिलायें हैं। कानून को धता बताते हुए दोनों प्लांटों में स्थाई प्रकृति के कामों पर 350 से अधिक श्रमिक ठेकेदारी पर काम करते हैं।

इन मज़दूरों को तमाम भत्ते आदि मिलाकर कुल 7300 रुपये मासिक वेतन मिलता आ रहा था जबकि हरियाणा सरकार का न्यूनतम ग्रेड 5800 रुपये मासिक का था। लेकिन जब हरियाणा सरकार ने इसे 1800 रुपये बढाकर 7600 रुपये कर दिया तो कम्पनी ने अपने श्रमिकों के तमाम भत्ते आदि काटकर कुल वेतन ग्रेड अनुसार कर दिया; अर्थात हरियाणा सरकार ने जो 1800 रुपये की बढोत्तरी की थी उसमें से कम्पनी ने 1500 की डंडी मार ली। श्रमिकों ने इसका विरोध किया, प्रदर्शन एवं गेट पर धरना आदि किया तो दिनांक 11 जनवरी को कम्पनी एवं ठेकेदार के बाऊंसरों ने गेट पर बैठी महिलाओं व पुरुष श्रमिकों की अच्छी खासी धुनाई कर दी। ऐसे में महिलाओं के साथ बद्तमीज़ी एवं अशलीलता होना स्वाभाविक है। कुछ को गंभीर चोटें भी लगी।

तमाम पीड़ित निकट ही स्थित गदपुरी पुलिस चौकी में शिकायत लेकर पहुंचे तो पुलिस ने कोई कार्यवाही करने की अपेक्षा उन्हें महिला थाना पलवल का रास्ता बता दिया जो कि नियम विरुद्ध है। अगले दिन जब पीड़ित महिला थाने पहुंचे तो उनसे पहले कम्पनी एवं ठेकेदारों ने भी पेशबंदी के तौर पर पीड़ितों के खिलाफ़ एक झूठी और बेबुनियाद शिकायत दे दी। कम्पनी की इस झूठी शिकायत को हथियार बना कर पुलिस ने असल पीड़ितों को डराना धमकाना शुरू कर दिया जिससे कि वे अपनी जायज शिकायत को वापस ले लें। पीड़ितों को डराने के लिये 14 जनवरी को उन्हें कई घंटे थाने में बैठाकर भी रखा गया और गिरफ़्तार करने की धमकी भी दी। जाहिर है यह सब कम्पनी एवं ठेकेदारों को खुश करने के लिये ही पुलिस कर रही थी।

शिक्षा का सत्यानाश करने की होड़

'गोद' के बहाने स्कूल बेचने की दौड़

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्कूलों के प्रबन्धन में पूरी तरह से विफ़ल हो चुकी खट्टर सरकार अब अपने स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने का षड़यन्त्र रच रही है। भ्रष्ट एवं निकम्मे राजनेताओं व अफ़सरों द्वारा शिक्षा बजट डकारने व पूरी शिक्षा व्यवस्था को तहस-नहस करने के बाद अब सरकार अपने तमाम स्कूल बड़े शिक्षा व्यापारियों के हवाले करने जा रही है। इस षड़यन्त्र को नाम दिया जा रहा है 'गोद देना'।

कोई पूछे जनता के इन दुश्मन नेताओं से कि कोई निजी स्कूल संचालक इनके स्कूलों को गोद क्यों लेगा और लेकर क्या करेगा? हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद भी जब सरकार स्कूलों को नहीं चला पा रही तो कोई निजी स्कूल इनके किसी भी स्कूल को कैसे चला पायेगा, जबकि निजी स्कूल संचालक अपने स्कूलों से भारी मुनाफ़ा कमाने के साथ-साथ बेहतर सुविधायें व शिक्षा अपने छात्रों को दे रहे हैं? जाहिर है पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड की तर्ज पर अब स्कूलों को भी सरकार 'गोद' मोड में डाल कर बेचने की तैयारी में है।

किसी भी सरकार के तीन मुख्य दायित्व-जान-माल की सुरक्षा, चिकित्सा तथा शिक्षा होते हैं। लेकिन गत 50 वर्षों से हरियाणा में आई विभिन्न दलों की सरकारों में शिक्षा का सत्यानाश करने में मानो एक होड़ सी लगी है। शिक्षा का बजट तो बढता जा रहा है परन्तु स्कूलों, शिक्षकों व छात्रों की संख्या दिन प्रति दिन घटती जा रही है। इतना ही नहीं जो शिक्षक तैनात हैं भी उन में से अधिकांश की योग्यता भी संदेह के दायरे में है। चौटालों द्वारा शिक्षक भर्ती घोटाला तो इसका एक उदाहरण मात्र है। गत बीसियों बरस से शिक्षकों की भर्ती का कोई नियमित तरीका नहीं अपनाया जा रहा। चौटाला राज में हुई शिक्षक भर्तियां अनियमितता का एक बड़ा नमूना है। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिये अतिथि अध्यापक का एक काम चलाऊ तरीका अपनाया गया। इससे पढाई का काम कम और सरकार के साथ मुकदमेबाज़ी का काम बढता गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य के किसी भी स्कूल में कुल जरूरत के आधे भी शिक्षक नहीं हैं, वह बात अलग है कि कुछ स्कूलों में किसी विषय विशेष के शिक्षक जरूरत से अधिक तैनात कर रखे हैं, राजनीतिक दबावों के चलते। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात और भी खराब हैं। वहां की बद्तर कार्यस्थितियों के चलते कोई भी शिक्षक वहां तैनात होना नहीं चाहता। किसी तरह की जुगाड़बाज़ी करके हर कोई शहरी क्षेत्रों में ही तैनाती चाहता है। 70 प्रतिशत से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां कोई नियमित मुखिया नहीं है।

इस सबके बावजूद हरियाणा सरकार शिक्षकों एवं स्टाफ़ आदि के वेतन पर 4900 करोड़ प्रति वर्ष खर्च दिखा रही है। बच्चों के बैठने के लिये न तो कहीं ढंग की इमारतें बची हैं और न ही उनमें बिजली पानी व शौचालय जैसी मौलिक सुविधायें हैं; फ़र्नीचर, लेबोरेट्री व पुस्तकालय आदि की तो बात ही छोड़ दो। इसके बावजूद सरकार वेतन के अलावा स्कूल भवनों व सुविधाओं के नाम पर 2000 करोड़ वार्षिक का खर्च दिखा रही है। यह अपने आप में एक बड़ा घोटाला है। जांच का विषय है कि आखिर यह इतनी बड़ी रकम जा कहां रही है? वैसे 'मज़दूर मोर्चा' ने अनेकों बार प्रकाशित किया है कि किस प्रकार स्कूलों के प्रिंसिपल व अन्य अधिकारी मिल बांट कर इन रकमों को डकारते हैं तथा शिकायतें होने पर कार्यवाही के नाम पर लीपा-पोती कर दी जाती है।

सरकारी स्कूलों में पढने वाले छात्रों की संख्या अधिकारिक तौर पर 21 लाख से अधिक बताई जा रही है; परन्तु वास्तविक संख्या 15 लाख से अधिक नहीं रह गयी है। शहरी क्षेत्रों की तो बात छोड़िये ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढाने लगे हैं। हां, यह बात अलग है कि सरकारी मास्टर जी अपनी नौकरी कायम रखने हेतु उन बच्चों के नाम अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं। इनके नाम पर आने वाला राशन-पानी मास्टरजी व अधिकारी मिल-बांट कर डकार लेते हैं। इसके अलावा स्कूलों में दूसरा बड़ा धंधा जाति विशेष के बच्चों को मिलने वाला वजीफ़ा है। इस तरह के अधिकांश बच्चों व उनके अभिभावकों की पढाई की अपेक्षा केवल वजीफ़े में ही रूचि रहती है। ऐसे बच्चे कभी-कभार ही स्कूल में प्रगट होते हैं। शिक्षा का नाश करने में कसर तो चौटालों व हुड्डा सरकार ने भी कोई नहीं छोड़ी थी, परंतु खट्टर की भगवा सरकार उनका भी रिकार्ड तोड़ने में जुटी है। कोई सुधार करने की बजाय इस सरकार ने 200 स्कूल इस वर्ष बंद कर दिये हैं और शिक्षा के नाम पर लूटने खाने के लिये 600 करोड़ का बजट और बढा दिया है। शिक्षा का स्तर बढाने की अपेक्षा साम्प्रदायिकता एवं अंधविश्वास को बढावा देने के लिये गीता पाठ का कार्यक्रम जरूर शुरू कर दिया है। मदरसों में धार्मिक ग्रंथ पढ-पढ कर अब तक तो मुस्लिम बच्चे ही पिछड़ेपन का शिकार हो रहे थे, अब यह भगवा सरकार बाकियों को भी बिगाड़ने पर तुली है।

सरकारी डाक सेवा केवल पासवानों के लिये रह गयी

फ़रीदाबाद (म.मो.) भारत सरकार का डाक महकमा और किसी की चिट्ठी-पत्री भले ही न पहुंचाये परन्तु केन्द्रीय मन्त्री राम बिलास पासवान जैसे अति-अति विशिष्टों की डाक तो पहुंचानी ही होगी। नहीं पहुंचाने अथवा ठीक से नहीं पहुंचाने वालों को ये लोग नौकरी में नहीं रहने देंगे।

पिछले दिनों राम बिलास पासवान ने हाजीपुर (बिहार) में अपने मिलने-जुलने वालों को नव वर्ष के शुभकामना पत्र भेजे थे जो प्राप्तकर्ताओं को मिल तो गये लेकिन थोड़ा विलम्ब से मिले। बस इतने पर डाकिये समेत 3 अधिकारियों को नौकरी से निलम्बित कर दिया गया। दरअसल जिन पतों पर ये पत्र आये थे वे बहुमंजिला इमारतों में थे। डाकिये का कसूर केवल इतना था कि उक्त वीआईपी पत्र ऊपरी मंजिल के बजाय निचली मंजिल पर डाल दिये गये। बस इतने में ही पत्र पाने वालों व भेजने वाले का तो बड़ा भारी अपमान हो गया।

पासवान समेत सारे शासक वर्ग से यह सच छिपा हुआ नहीं रह सकता कि कुल डाक का करीब एक चौथाई तो कभी गनतव्य तक पहुंचता ही नहीं। 24 घंटे में पहुंचने वाली स्पीड पोस्ट हरियाणा के ही एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने में 4 से 6 दिन ले लेती है, कोई पूछने वाला नहीं। पासवान की डाक तो केवल शुभकामना जैसी फ़िजूल की डाक थी जिसके पहुंचने न पहुंचने से किसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब लोग़ों की परीक्षा एवं नौकरी सम्बन्धी डाक गुम हो जाती है या समय गुजरने के बाद पहुंचती है तो लोग़ों पर क्या बीतती है, यह जानने की कोशिश कोई पासवान नहीं करता। करीब 30 वर्ष पूर्व तक भारत का डाक-तार विभाग एक आदर्श विभाग था। इसमें भ्रष्टाचार का नामोनिशान नहीं था और कार्यकुशलता में बेमिसाल था, तमाम कर्मचारी/अधिकारी पूरी निष्ठा व लग्न से काम करते थे। परन्तु बीते वर्षों में आई सरकारों ने खूब जम कर इस विभाग का सत्यानाश किया है। कर्मचारियों की छटनी करके आर एम एस (रेलवे मेल सर्विस) को तो बिल्कुल ही मार डाला। घरों में डाक बांटने वाले डाकियों का क्षेत्र बढता गया और इनकी संख्या घटती गयी। नये भर्ती करने की बजाय अल्पकालिक कैजुअल डाकिये रखने शुरू कर दिये, जब तक ये काम को समझ पाते हैं तब तक उनके हटने का समय आ जाता है।

कम्प्यूटर व इन्टरनेट लगा तो दिये जो आधे समय खराब ही रहते हैं। बिजली समस्या से निपटने के लिये जनरेटर सेट खरीद कर तो रख दिये लेकिन वे चलते नहीं। उनमें या तो तेल नहीं होता या कोई पुर्जा खराब रहता है। सम्बन्धित अधिकारियों की नीयत काम करने की बजाय तिकड़मबाज़ियों में अधिक रहती है। इसके बरक्स निजी डाक सेवा (कूरियर) दिन दूणी रात चौगुणी उन्नत्ति कर रही है और मोटा मुनाफ़ा कमा रही है। लगता है कि शासक वर्ग कूरियर सेवाओं को लाभान्वित करने की साजिश के तहत ही अपनी (सरकारी) डाक सेवा का बेड़ा गर्क करने पर तुला है।

सुप्रसिद्ध मज़दूर नेता कामरेड दर्शन सिंह नहीं रहे

हरियाणा के कमयुनिष्ट मज़दूर नेता कामरेड दर्शन का 85 वर्ष की उम्र में 8/1/2016 को निधन हो गया। का. सिंह काफ़ी समय से बिमार चल रहे थे। राष्ट्रीय स्तर पर एटक के कोषाध्यक्ष भी रहे। का. दर्शन सिंह के निधन से हरियाणा के मज़दूर व वामपंथी आंदोलन को गम्भीर क्षति पहुंची है। वे अपने वेचारिक प्रतिबद्धता के साथ-साथ मज़दूर आन्दोलन में एक व्यवहारिक नेता के तौर पर स्थापित थे।

का. दर्शन सिंह का जन्म लाहौर ज़िला के संतपुरा ग्राम (पाकिस्तान) में 15 अगस्त 1930 को हुआ था। इनके पिता सरदार गोपाल सिंह एक जमींदार थे। का. दर्शन सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर से मैट्रिक किया। विभाजन के बाद लाहौर से अमृतसर आ गये और बाद में दिल्ली के पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनिरिंग में डिप्लोमा किया। इसके बाद ये भाखड़ा नंगल डैम में सुपरवाईजर की नौकरी में लग गये। वहां भी एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा एक मज़दूर को गाली देने पर इन्होंनें उसके कार्यलय में ही उसे पीट दिया जिसके चलते नौकरी भी गई और गिरफ़्तारी भी हो गई। बाद में मज़दूरों ने हड़ताल कर दी तो रिहा करना पड़ा। इस घटना के बाद इन्होंने नौकरी का ईरादा त्याग दिया तथा पंजाब पार्टी के पुरा वक्ती कार्यकर्ता बन कर ट्रेड यूनियन के मोर्चे पर काम करने लगे। पंजाब में इन्होंने बाबा करतार सिंह, हरकिशन सिंह 'सुरजीत' का. सतीश लुम्बा आदि के साथ काम किया।

1965 में पार्टी ने इन्हें फ़रीदाबाद में स्थानांतरित कर दिया। हरियाणा बनने के बाद इन्होंने हरियाणा के दिग्गज नेताओं कामरेड हर नाम सिंह, चौ. रघुबीर सिंह का. बलदेव बक्सी आदि के साथ काम किया। फ़रीदाबाद की बड़ी लड़ाईयों में एस्कॉर्टस, ईस्ट इंडिया, बाटा, आदि की लम्बी-लम्बी हड़तालों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। 1973 के गुडइयर गोली कांड, और बाद में 1979 में नीलम चौक गोली कांड में अगुआ भूमिका में रहे। इसी कांड में अन्य नेताओं के साथ इन पर भी हरियाणा सरकार ने पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप लगाते हुये 302 का मुकदमा दायर किया था। काफ़ी दिनों तक भूमिगत रहने के बाद उच्च न्यायालय ने अन्तिरिम जमानत दे दी। का. दर्शन सिंह अपने पीछे पत्नी कामरेड सुशीला, पुत्र विजेन्द्र सिंह और दो पोते छोड़ गये हैं।

हरियाणा एटक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ज़िला परिषद्, अपने नीडर, साहसी, स्पष्ट व प्रखर वक्ता, अपने सिद्धान्तों के प्रति निष्ठावान नेता का. दर्शन सिंह को श्रद्धा के सुमन अर्पित करती है और उनकी याद में अपना झंडा झूकाती है।

बेचू गिरी, महासचिव-
हरियाणा राज्य एटक